

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.07.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1831 का उत्तर

स्टेशनों में वाई-फाई सुविधा

1831. श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ऐसे रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें आज की तिथि तक वाई-फाई सुविधा प्रदान की गई है;
- (ख) इन स्टेशनों में वाई-फाई के संचालन के तरीके का ब्यौरा क्या है और निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत अब तक कितने स्टेशनों में यह सुविधा अधिष्ठापित की गई है;
- (ग) वाई-फाई की स्थापना के लिए चुने गए स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है और ये स्टेशन किन-किन राज्यों में आते हैं; और
- (घ) इन स्टेशनों का चयन किन मानदंडों के आधार पर किया गया था?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) अब तक, 6102 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) इन सभी वाई-फाई सुविधाओं के दैनिक संचालन का प्रबंधन (रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) (रेल मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) द्वारा किया जाता है।

निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के तहत कोई वाई-फाई प्रदान नहीं किया गया है।

बहरहाल, निजी संगठनों के सहयोग से निम्नलिखित 416 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई मैसर्स गूगल के साथ साझेदारी में और 4412 स्टेशनों मैसर्स टाटा ट्रस्ट द्वारा धर्मार्थ कार्य के रूप में प्रदान किए गए हैं।

(ग) और (घ) ऑप्टिकल फाइबर केबल और अन्य संसाधनों जैसी अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर हॉल्ट को छोड़कर सभी स्टेशनों पर वाई-फाई प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब तक, 6102 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। राज्य-वार सूची परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

स्टेशनों में वाई-फाई सुविधा के संबंध में 27.07.2022 को लोक सभा में श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी के अतारांकित प्रश्न सं. 1831 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट।

क्र.सं.	राज्य का नाम	उन स्टेशनों की संख्या जहां पीपीपी के तहत वाई-फाई
1	आंध्र प्रदेश	508
2	अरुणाचल प्रदेश	3
3	असम	222
4	बिहार	397
5	छत्तीसगढ़	119
6	दिल्ली	26
7	गोवा	19
8	गजरात	334
9	हरयाणा	146
10	हिमाचल प्रदेश	24
11	जम्म और कश्मीर	28
12	झारखंड	215
13	कर्नाटक	335
14	केरल	119
15	मध्य प्रदेश	415
16	महाराष्ट्र	550
17	मेघालय	1
18	मिजोरम	1
19	नागालैंड	3
20	ओडिशा	234
21	पंजाब	151
22	राजस्थान	462
23	तमिलनाडु	416
24	तेलंगाना	47
25	त्रिपरा	18
26	केंद्र शासित प्रदेश	1
27	केंद्र शासित प्रदेश	3
28	उत्तर प्रदेश	768
29	उत्तराखंड	30
30	पश्चिम बंगाल	507
	कुल	6102
